भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 278 का उत्तर

बेंगलुरु में उपनगरीय रेल नेटवर्क

***278. श्री तेजस्वी सूर्या:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना की धीमी प्रगति को देखते हुए बेंगलुरु में उपनगरीय रेल नेटवर्क का कार्यान्वयन और संचालन स्वयं करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में रेल परियोजनाओं, कंपनियों या विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के सरकारी-निजी भागीदारी और केंद्र-राज्य भागीदारी के कितने मॉडल कार्यरत हैं;

(घ) ऐसे मॉडलों के लाभकारी उपक्रमों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मॉडलों के सफल न होने के कारण यदि कोई हैं, तो वे क्या हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 19.03.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 278 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (के-राइड), जो कर्नाटक राज्य सरकार (51% इक्विटी) द्वारा नियंत्रित एक कंपनी है, बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) को निष्पादित कर रही है। बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (148.17 किमी) को ₹15767 करोड़ की लागत पर स्वीकृति दी गई है, जिसमें भारत सरकार और कर्नाटक सरकार प्रत्येक द्वारा 20% वित्तपोषण किया जाएगा और 60% वित्तपोषण ऋण के माध्यम से किया जाएगा।

बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना में चार गलियारे हैं, नामतः,

गलियारा-1: केएसआर बेंगलुरु सिटी-देवनहल्ली (41.4 किलोमीटर)
गलियारा-2: बायपनहल्ली - चीक्कबाणावार (25.01 किलोमीटर)
गलियारा-3: केंगेरी-व्हाइटफील्ड (35.52 किलोमीटर)
गलियारा-4: हीललिगे-राजनकुंटे (46.25 किलोमीटर)

गलियारा-2 और 4 पर कार्य प्रगति पर है। गलियारा 1 और 3 के लिए के-राइड द्वारा प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। भारतीय रेल ने परियोजना के लिए रेल भूमि के-राइड को हस्तांतरित कर दी है, बहरहाल, राज्य सरकार की भूमि के हस्तांतरण की प्रगति बहुत धीमी है।

इसके अलावा, वर्तमान में, कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक प्रबंध निदेशक परियोजना का कार्य देख रहे हैं। इस परियोजना के लिए एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता है, जो रेल प्रौद्योगिकी से परिचित हों।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, अतिलंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना/परियोजनाओं के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि। ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

अब तक, केंद्र-राज्य भागीदारी वाली 9 राज्य संयुक्त उद्यम कंपनियाँ हैं। इनमें गैर-सरकारी रेलवे (एनजीआर), संयुक्त उद्यम (जेवी), ग्राहक-वित्तपोषित (सीएफ), निर्माण-स्वामित्व-हस्तांतरण (बीओटी) और वार्षिक वृत्ति सहित कई सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल हैं। अभी तक, इन मॉडलों में, 19 परियोजनाओं में कार्य पूरा हो चुका है और 12 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

इन संयुक्त उद्यम/विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) रेल परियोजनाओं में से, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, 6 एसपीवी परियोजनाएँ लाभप्रद हैं और शेष परियोजनाएँ निर्माण/संचालन के विभिन्न चरणों में हैं।

*****